

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2336 / 2010 / जयपुर
2. अपील संख्या 2337 / 2010 / जयपुर
3. अपील संख्या 2338 / 2010 / जयपुर

मैसर्स कम्प्यूएज इन्फोकॉम लि०,
ई-1, रामनगर एक्सटेंशन, सोडाला, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम
सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक।
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक।

.....व्यवसायी की ओर से
.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.03.2017

निर्णय

1. यह तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 26.8.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन प्रथम, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने पर अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है, अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अ.सं.	कर नि. आ. दि.	कर निर्धा.वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
2336/10	95/200	15.02.10	2007-08	6,89,878/-	41,395/-	13,79,756/-
2337/10	94/201	15.02.10	2008-09	9,07,166/-	1,45,150/-	18,14,332/-
2338/10	93/101	15.02.10	2009-10	12,43,303/-	3,48,125/-	24,86,606/-

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत प्रथम, जयपुर द्वारा दिनांक 22.01.2010 को किया गया था। जिसमें पाया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा मल्टीफक्शन प्रिन्टर का विक्रय 4 प्रतिशत की कर दर से किया जाकर टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि उक्त वस्तु पर कोई कर दर घोषित नहीं की गई है, अतःएव इस पर सामान्य कर दर पर करारोपण किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी कम्पनी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने व्यवहारी पर आरोपित कर, ब्याज शास्ति को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।
4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उनके द्वारा विक्रीत वस्तु मल्टीफक्शन अधिनियम की अनुसूची IV के आईटम संख्या 3 के अंतर्गत आती है, परन्तु अपीलीय अधिकारी ने अविधिक तौर पर इसको 12.5 प्रतिशत अनुसूची V में शुमार माना है इसके समर्थन में उन्होंने हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इसी वस्तु पर

लगातार.....2

दिये गये निर्णय RGSTR 103(RHC) Ms Kores (India) Limited Vs The Assistant Commissioner, Anti Evasion Raj.7-Jaipur Decided on February 19, 2016 का उद्धरण प्रस्तुत किया एवं कथन किया कि उनके द्वारा बिक्रीत मल्टीफंक्शन मशीन पर अधिनियम की अनूसूची IVA के अंतर्गत कम्प्यूटर पैरीफैरलस होने के कारण 4 प्रतिशत से कर योग्य है तदनु रूप सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत मल्टीफंक्शन मशीन पर 4 प्रतिशत से कर चुकाया है जबकि इस पर तत्समय 12.5 प्रतिशत कर देयता थी इस प्रकार जानबूझकर कर नजरअंदाज किया गया है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा किया गया करारोपण उचित होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिक है। तदनु रूप व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जायें एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को पुनर्स्थापित किया जावें।

7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RGSTR 103(RHC) Ms Kores (India) Limited Vs The Assistant Commissioner, Anti Evasion Raj.7-Jaipur Decided on February 19, 2016 का अवलोकन किया गया जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि :-

"The term "peripheral" has been defined in Oxford Dictionary to mean as under :-

(of a device) able to be attached to and used with computer, though not an integral part of it."

17. A multi-functional machine can be a computer peripheral, if its principal or sole purpose is to be attached and function as a computer ancillary. A multi-functional machine will be and qualify as a Computer peripheral when its main/predominant purpose is to scan documents, load data or work as an input device of the computer or work as an output device to take printouts, etc., from the computer. At the same time, there can be photo copiers, whose main purpose is to copy or act as duplicating machine to make copies of documents. Incidentally, they may also be used as a printer. This would, require elucidation and examination of factual matrix in each case and the machine in question on case to case basis."

Therefore upon a detailed analysis and with reference to various technical literature and material, the cases laws in favour of the Assessee, this court is satisfied that the commodity in question, namely. Multi-functional device could not be taxed by the Assessing Authority under the Residuary Entry for the period from 01.04.2006 to 09.03.2010, and the said commodity would fall within the ambit and scope of relating to computer printers and computer peripherals, taxable entry 4% in Schedule IV of the VAT Act."

8. उपरोक्त निर्णय अपीलार्थी कम्पनी द्वारा विक्रय किये गये मल्टीफंक्शन डिवाइसेज पर ही दिया गया है, जो हस्तगत प्रकरण में शत-प्रतिशत लागू होता है। अतः कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय अपास्त किये जाते हैं।

माननीय कर बोर्ड के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्-बी' उदयपुर; (2012) 33 टैक्स अपडेट 270 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्-सी' जोधपुर बनाम मैसर्स मिर्चूमल इलेक्ट्रॉनिक्स; (2012) 34 टैक्स अपडेट 117 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्-जालोर बनाम मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार; टैक्स डाइजेस्ट वॉल्यूम-1 पार्ट-1 पेज 31 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत् जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य एवं (2014) 40 अपडेट 203 सहायक आयुक्त, वृत्-ए, भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।


9. जहां तक शास्ति के बिन्दु का प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है :-


"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

चूंकि ये अपीलें वस्तुओं के निर्वचन से संबंधित हैं एवं समस्त बिक्री अपीलार्थी कम्पनी ने अपने रिकार्ड तथा विवरणियों में प्रदर्शित की हैं। अतः करापवचन की मंशा नहीं होने एवं माननीय उच्चतम न्यायालय उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार शास्ति का आरोपण हस्तगत प्रकरणों में विधिनुकूल नहीं ठहरने से प्रस्तुत अपीलें शास्ति के बिन्दु पर स्वीकार योग्य पायी जाती हैं।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


23.3.2017
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष